

NEXT IAS

दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भारत
की प्रतिबद्धता

www.nextias.com

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भारत की प्रतिबद्धता

सन्दर्भ

- भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (SFDRR) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है, जो 2015 में अपनाया गया संयुक्त राष्ट्र समर्थित वैश्विक समझौता है।
 - इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य समुदायों और राष्ट्रों के जीवन, आजीविका और परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए आपदा जोखिमों और हानियों में पर्याप्त कमी लाना है।

भारत की आपदा जोखिम न्यूनीकरण पहल के प्रमुख आयाम

- **सेंडाई फ्रेमवर्क सिद्धांतों को अपनाना:** सेंडाई फ्रेमवर्क कमज़ोरियों को कम करने और लचीलापन बढ़ाने पर बल देता है। भारत ने इन सिद्धांतों को राष्ट्रीय नीतियों में शामिल किया है, जैसे कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP), जो सेंडाई के चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के साथ निकटता से जुड़ी हुई है:
 - आपदा जोखिम को समझना
 - आपदा जोखिम प्रशासन को मजबूत करना
 - लचीलेपन के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) में निवेश करना
 - प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आपदा तैयारी को बढ़ाना
- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक साझेदारी:** भारत ज्ञान साझाकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आपदा लचीलेपन पर संयुक्त पहल को बढ़ावा देता है।
 - उदाहरण के लिए, भारत द्वारा शुरू किए गए आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (CDRI) में अब 40 देश और सात अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। यह पहल सेंडाई फ्रेमवर्क के अनुरूप है।
- **क्षेत्रीय और स्थानीय लचीलेपन को मजबूत करना:** भारत की राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (NCRMP) और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG), जो बाढ़ और सूखे के जोखिमों से निपटते हैं, प्रासंगिक आपदा लचीलेपन के सेंडाई सिद्धांत के अनुरूप हैं।
 - गुजरात और अन्य राज्यों में लागू की गई हीट एक्शन प्लान का उद्देश्य अत्यधिक गर्मी की लहरों से होने वाले खतरों को कम करना है।
- **आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वित्तपोषण बढ़ाना:** भारत ने आपदा वित्तपोषण को प्राथमिकता दी है, जिसे प्रायः अनदेखा किया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) त्वरित प्रतिक्रियाओं और दीर्घकालिक लचीलापन निर्माण के लिए संसाधन आवंटित करते हैं।
 - G-20 में भारत ने DRR वित्तपोषण को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया तथा पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करते हुए जोखिमों को कम करने के लिए लागत प्रभावी दृष्टिकोण के रूप में प्रकृति-आधारित समाधान (NbS) का प्रस्ताव रखा।
- **उदाहरण:** पुणे में मुला-मुथा नदी पर हाल ही में शुरू की गई बाढ़ के मैदानों की पुनर्स्थापन परियोजना का उद्देश्य आर्द्रभूमि को पुनर्स्थापित करके बाढ़ के लचीलेपन के लिए NbS का उपयोग करना है, जो अतिरिक्त वर्षा को अवशोषित करता है, कटाव को कम करता है, और भूजल को फिर से भरता है।

G-20 बैठक में भारत की पांच DRR प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला गया

- **प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली:** चक्रवातों और उष्ण वायु के लिए भारत की प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों ने आपदा की तैयारियों के लिए मानक स्थापित किए हैं। यह चक्रवात तौकते के दौरान प्रदर्शित किया गया था, जहाँ समय पर अलर्ट ने मृत्युओं को कम करने में सहायता की।

- **आपदा-प्रतिरोधी अवसंरचना:** CDRI के माध्यम से, भारत बाढ़, भूकंप और चक्रवातों का सामना करने वाले लचीले अवसंरचना के निर्माण में वैश्विक समुदायों की सहायता करता है।
- **आपदा वित्तपोषण:** भारत ने DRR वित्तपोषण बढ़ाने, इसे नीति नियोजन में एकीकृत करने और संसाधन उपलब्धता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्राप्त करने पर बल दिया।
- **लचीला पुनर्प्राप्ति:** भारत पुनर्निर्माण प्रयासों में लचीलेपन को शामिल करते हुए बेहतर निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए आपदा के बाद की पुनर्प्राप्ति का समर्थन करता है। 2018 की बाढ़ के बाद केरल में पुनर्निर्माण एक उदाहरण है, जिसमें बाढ़-प्रतिरोधी अवसंरचना और भवन मानकों को शामिल किया गया है।
- **प्रकृति-आधारित समाधान (NbS):** भारत आर्द्रभूमि पुनर्स्थापना और वनरोपण जैसे NbS को स्थायी उपायों के रूप में बढ़ावा देता है जो जैव विविधता को संरक्षित करते हुए आपदा प्रभावों को कम करते हैं।

भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण में चुनौतियां और अंतराल

- **वित्तपोषण संबंधी बाधाएँ:** प्रयासों के बावजूद, आपदा वित्तपोषण सीमित बना हुआ है, तथा DRR के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी अभी भी विकसित हो रही है।
- **बुनियादी ढाँचा भेद्यता:** शहरी क्षेत्रों को प्रायः उच्च-तीव्रता वाली आपदाओं का सामना करने के लिए नहीं बनाया जाता है। पर्याप्त जोखिम आकलन के बिना तेज़ी से शहरीकरण भेद्यता को बढ़ाता है।
- **डेटा और अनुसंधान:** स्थानीय आपदा जोखिम डेटा और जलवायु-प्रेरित आपदाओं जैसे उभरते जोखिमों पर उन्नत अनुसंधान की आवश्यकता है।
- **प्रकृति-आधारित समाधानों का कार्यान्वयन:** NbS के लिए सावधानीपूर्वक योजना और दीर्घकालिक निवेश की आवश्यकता होती है, लेकिन सीमित संसाधन और प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताएँ कार्यान्वयन को धीमा कर सकती हैं।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण को सुदृढ़ करने के लिए आगे की राह

- **DRR वित्तपोषण में वृद्धि:** आपदा जोखिम वित्तपोषण के लिए अधिक मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी स्थापित करें, संवेदनशील क्षेत्रों के लिए लक्षित निधि बनाएं और कर प्रोत्साहनों के माध्यम से DRR में निवेश को प्रोत्साहित करें।
- **CDRI और वैश्विक गठबंधनों का विस्तार करें:** CDRI को मजबूत करना जारी रखें और समान आपदा चुनौतियों का सामना करने वाले देशों के साथ नए सहयोग की खोज करें, वैश्विक ज्ञान विनिमय तथा क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करें।
- **स्थानीयकृत प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों पर ध्यान दें:** समुदाय-विशिष्ट प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को बढ़ाएँ, विशेष रूप से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन के लिए।
- **लचीले शहरी नियोजन में निवेश करें:** कमजोरियों को कम करने के लिए सख्त भवन संहिताओं को लागू करें, क्षेत्रीकरण कानूनों को लागू करें और जलवायु-लचीले शहरी बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहित करें।
- **अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाएँ:** उभरते जोखिमों का अनुमान लगाने और उन्हें संबोधित करने के लिए जलवायु-लचीले फसलों, पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढांचे और बाढ़ प्रबंधन प्रौद्योगिकियों सहित आपदा अनुसंधान में निवेश करें।

- **प्रकृति-आधारित समाधान (NbS) को बढ़ावा दें:** जोखिमों को स्थायी रूप से प्रबंधित करने के लिए तटीय, नदी और वन क्षेत्रों में NbS परियोजनाओं का विस्तार करें, इन समाधानों को व्यापक विकास योजनाओं में एकीकृत करें।



दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. "भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई है, लेकिन व्यापक लचीलापन प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सेंड्राई फ्रेमवर्क के अनुरूप आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भारत के दृष्टिकोण पर चर्चा करें।

